कपड़े का मूल्य

*643. श्री रामसेवक यादव :
श्री किशन पटनायक :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कपड़े को जो कीमत लौ जाती है और कपड़े पर छपी होती है, वह कपड़े के कारखाना से निकलने के मूल्य पर कुछ प्रतिशत छूट देने के बाद नियमों के अधीन स्वीकृत मूल्य से अधिक है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उस नियम का, जिसके अनुसार कट-पीस कपड़े का मूल्य कारखाना से निकलने के मूल्य से 6¼ प्र० श० कम होना चाहिये, निरन्तर उल्लंघन किया जा रहा है और कट-पीस कपड़े पर कोई भी छूट नहीं दी जाती ; और

(ग) यदि हां, तो क्या अधिक मूल्य लिये जाने पर रोक लगाने के बारे में कोई कार्यवाही करने का विचार किया जा रहा है ?

वाणिज्य उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) से (ग). कपड़े की नियंत्रित किस्मों अर्थात् धोतियों, साड़ियों, लट्ठे, कमीजों के कपड़ तथा जीन के कारखाने से निकलने की अधिकतम और खुदरा कीमतें वस्त्र आयुक्त द्वारा निर्दिष्ट की गयी हैं और वे कपड़े की नियंत्रित किस्मों पर छपी होती हैं । नियन्त्रित कपड़े की प्रत्येक किस्म पर छपी हुई कीमत की विस्तृत गणना की सूचना वस्त्र आयुक्त को दी जाती है और वे उसकी जांच करते हैं। वस्त्र आयुक्त के संगठन की प्रवर्तन शाखा यह सुनिश्चित करने के लिये जांच पड़ताल करती है कि मिलों ने कीमत तथा अन्य छापें नियत तरीके से अंकित की हैं । वस्त्र आयुक्त द्वारा निर्दिष्ट कीमतों से अधिक कीमतें अंकित करना सूती वस्त्र नियंत्रण आदेश का उल्लंघन होता है। हजारों निरीक्षणों तथा जांचों में से कुछ मामलों में ही कपड़े पर छपी कीमतों का हिसाब लगाने में थोड़ी सी त्रुटियां पाई गई हैं । इस प्रकार निर्दिष्ट कीमतों के अंकन में कोई उल्लंघन नहीं हुआ है ।

वस्त्र आयुक्त द्वारा निर्दिष्ट की गई कीमतों से अधिक कीमत लेना सूती कपड़ा नियंत्रण आदेश 1948 का उल्लंघन करना होता है। समस्त देश के व्यापारियों की भारी संख्या में कहीं ही नियंत्रित वस्त्रों की अधिक कीमत लेने के उदाहरण देखने में आये हैं ।

2½ गज से कम के कट-पीस की कीमत का कोई नियंत्रण नहीं किया जाता । 2½ गज से बड़े किन्तु 10 गज से छोटे कपड़े (जिसे तकनीकी दृष्टि से सेकेण्डस कहते हैं) कीमत उस कपड़े के अधिक लम्बे टुकड़े के कारखाने से चलते समय की कीमत से 10 प्रति शत कम होती है । कपड़े की कट-पीस पर कोई छूट नहीं दी जाती ।

Establishment of Woollen Textile Mills in Ethiopia

*644. **Shri Indrajit Gupta:** Will the Minister of Commerce be pleased to state:

(a) whether approval has been given to Messrs. Duncan Bros. and Co., Ltd. to establish a woollen textile mill in Ethiopia in collaboration with the Ethiopian nationals;

(b) whether Messrs. Anglo-India Jute Mills Co., Ltd. have proposed to invest Rs. 5.25 lakhs in the said venture's equity shares; and

(c) if so, whether Government are satisfied that the present financial state of the Anglo-India Jute Mills Co., with particular reference to the returns earned by it on other investments, justifies further investment of its assets in the Ethiopian venture?